मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में श्रावण मास में आयोजित झूला महोत्सव में बहनों को झूला झुलाया।

सीलिंग के विरोध में व्यापारियों का चक्काजाम

मास्टर प्लान और नियमितीकरण की मांग, कार्रवाई नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने रोशनपुरा चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। करीब पौने दो घंटे चले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। महिलाओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

व्यापारियों ने सरकार से भोपाल का मास्टर प्लान जल्द लागू करने, मिश्रित भू-उपयोग का प्रावधान करने और गुजरात की तर्ज पर अनधिकृत विकास नियमितीकरण कानून लागू करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ व्यापारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। व्यापारियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान भी गाया। विरोध जताने के लिए एक ब्यूटीशियन ने सड़क पर ही मेकअप किया। व्यापारियों का कहना है कि सीलिंग कार्रवाई से दुकानदारों के साथ कर्मचारियों और उन पर निर्भर परिवारों का रोजगार प्रभावित होगा।

व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने सरकार से त्योहारों से पहले राहत देने की मांग भी की। इधर, नगर निगम ने आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 6,589 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। करीब 750 मामलों में अंतिम सूचना दी जा रही है। इसके बाद भी व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहने पर प्रतिष्ठान सील किए जा सकते हैं।

नगर निगम के अनुसार शहर में 62 हजार 500 से अधिक ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जहां रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। निगम का कहना है कि नोटिस की संख्या आगे बढ़ सकती है।

फेक न्यूज़ के दौर में पत्रकारिता की जिम्मेदारी बढ़ी : डॉ. यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि फेक न्यूज के दौर में पत्रकारों को नेक न्यूज और सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। पत्रकारिता में सत्ता का विरोध उचित है, लेकिन देश विरोध नहीं होना चाहिए। हमारे लिए न्यूज से ऊपर नेशन यानी राष्ट्रहित होना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सत्रारंभ-अभ्युदय 2026 कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और इस विश्वविद्यालय ने देश को कई प्रतिभाशाली पत्रकार दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के प्रकाशनों 'दो सदी साक्षी', 'मैं न्यूज़ रूम' और 'इंडियन कलाईडोस्कोप' का विमोचन किया। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया और '100 साल से 100 सुर्खियां' प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल तक पत्रकारों ने लोकतंत्र और सच्चाई की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में संचार की परंपरा प्राचीन काल से रही है। विद्यार्थियों को नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ देश निर्माण में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी, अभिनेता व साहित्यकार पीयूष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अधिकारी उपस्थित रहे।

महँगाई भत्ते और सीपीसीटी की अनिवार्यता के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आठ माह से लंबित महंगाई भत्ते और सीपीसीटी की अनिवार्यता के विरोध में तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने मंगलवार को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया और जल्द कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने की मांग की।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदर्शन में संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने प्रदेश में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की मांग की।

कर्मचारियों ने नवनियुक्त कर्मचारियों को तीन साल तक 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने के प्रावधान को समाप्त कर 100 प्रतिशत वेतन देने की मांग की। संघ के अनुसार, इस व्यवस्था से प्रत्येक कर्मचारी को करीब 1.74 लाख से चार लाख रुपये तक का आर्थिक नुकसान होता है।

मंत्रालय के सामने नारेबाजी कर जताया विरोध, कैशलेस स्वास्थ्य योजना जल्द लागू करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन इसका लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। संघ ने योजना को जल्द लागू करने की मांग की।

कर्मचारियों ने सीधी भर्ती में सीपीसीटी की अनिवार्यता रखे जाने पर सहमति जताई, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति और चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए इसकी बाध्यता समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा ई-अटेंडेंस व्यवस्था खत्म करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा ने किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सलीम खान सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

लाइव सर्जरी से ईएनटी विशेषज्ञों ने सीखी जटिल मामलों की बारीकियाँ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः दिव्य एडवांस ईएनटी क्लीनिक में आयोजित 19वें 'बैक टू बेसिक' कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में देशभर से आए ईएनटी विशेषज्ञों ने जटिल सर्जरी तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर अनुभव साझा किए।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश और प्रदेश के सैकड़ों ईएनटी सर्जनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान क्लीनिक में लाइव सर्जरी की गईं, जिनका सीधा प्रसारण जहनुमा पैलेस में मौजूद चिकित्सकों को दिखाया गया। जयपुर के वरिष्ठ सर्जन डॉ. सतीश जैन ने सीएसएफ राइनोरिया क्लोजर, घेंघा रोग, कान और साइनस से जुड़ी जटिल सर्जरी की। दूसरे दिन उन्होंने नाक की दो सर्जरी के साथ इमेजिंग विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। लाइव सर्जरी के माध्यम से चिकित्सकों को ऑपरेशन की तकनीक, निर्णय लेने की प्रक्रिया और जटिल मामलों के प्रबंधन को करीब से समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम में बैंगलोर के डॉ. दीपक हल्दीपुर, मिरज के डॉ.

सुधीर कदम, मुंबई के डॉ. मिनेश जुवेकर और डॉ. मिलिंद नवलखे, अमृतसर के डॉ. जसकरन सिंह तथा आगरा के डॉ. राजीव पचौरी ने विभिन्न चिकित्सकीय विषयों पर व्याख्यान दिए। विशेषज्ञों ने ईएनटी सर्जरी में आधुनिक तकनीकों, जटिल मामलों के उपचार और बेहतर क्लिनिकल परिणामों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर चर्चा की।

कार्यक्रम में एओआई के पास्ट प्रेसिडेंट डॉ. दीपक हल्दीपुर, डॉ. नंदू कोलवरकर और डॉ. सुधाकर वैद्य सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के ईएनटी विभागाध्यक्ष और कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिव्य एडवांस ईएनटी क्लीनिक के युवा चिकित्सक डॉ. दिव्य प्रकाश दुबे ने किया। आयोजन सचिव एवं एओआई के पास्ट प्रेसिडेंट डॉ. संजय अग्रवाल ने अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

मंत्रालय की गुफ्तगु...

डॉ. शिशिर उपाध्याय

• अवैध उत्खनन पर कार्रवाई पड़ी भारी...

पिछले दिनों एक जिले में कलेक्टर-कमिश्नर ने जोश-जोश में अपने क्षेत्र में अवैध माइनिंग और उत्खनन रोकने के निर्देश दिए। निचले स्तर के अधिकारियों ने साहब के निर्देश को गंभीरता से लिया और कुछ जगहों पर छापा मारकर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। जहां कार्रवाई की गई, वहां वे बहुत पावरफुल थे। अवैध उत्खनन करने वालों ने सरकारी अधिकारियों, जिन्होंने कार्रवाई की थी, उन्हें ही हटवा दिया।

• पर्यावरण से खिलवाड़, ऊपर से रोकना भारी पड़ रहा

मध्यप्रदेश सरकार और उसके मुखिया मध्यप्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कम-से-कम हो, यह फरमान भी समय-समय पर जारी होता है। लेकिन मंत्रालय के सभी चेंबरों में पानी अब गिलास में नहीं, बोतलों में ही सर्व किया जाता है। जब मंत्रालय में ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर इतनी घोर लापरवाही है तो प्रदेश का क्या हाल होगा? इसलिए कहते हैं कि कागजी कार्रवाई और बयान अलग-अलग होते हैं। पर नामी-गिरामी कंपनी का पानी भी जरूरी है।

• साहब का सूट सिला का सिला रह गया

15 अगस्त पर ध्वजारोहण करने के लिए कुछ जिलों में माननीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ जिलों में कलेक्टर साहब को ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री जी के भाषण का वाचन करना था। लेकिन अचानक कुछ मंत्रियों के जिलों में हुए बदलाव ने एक युवा अधिकारी के सपनों पर पानी फेर दिया। उन्होंने जोधपुरी सूट सिलवाकर पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक हुए बदलाव ने उन्हें दर्शक बना दिया।

• काश हम न हुए होते...

एक जिले में जनविश्वास अभियान के दौरान प्रभारी के रूप में पहुंचे आला अधिकारी ने जिले में दौरे के दौरान बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं और जिला कलेक्टर की लापरवाही को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी-खोटी सुनाई। युवा कलेक्टर अभी जिले में पहुंचे हैं, उन्हें बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जिलाधीश को वरिष्ठ अधिकारी की करतूतें बताईं तो उन्होंने कहा, 'काश हम न हुए होते उस समय, नहीं तो वहीं सब हिसाब-किताब कर देते, फिर आवाज ही बंद हो जाती।'

• साहब की सज्जनता और समकक्षों का व्यवहार

मध्यप्रदेश के एक संभागीय मुख्यालय पर बड़े साहब बहुत ही संवेदनशील और आम जनता के लिए सदैव तत्पर रहने के कारण उनके क्षेत्र में पदस्थ कुछ माननीयों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों बड़े साहब के व्यवहार से परेशान एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने साहब को दो टूक कहा कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से कुछ व्यवहारिकता सीख लीजिए, कैसे जनता से संवाद किया जाता है। साहब की परेशानी यही है कि बड़े साहब की संवेदनशीलता और व्यवहार अब जिले के मुखिया को खटकने लगा है।

• कोर्ट की फटकार और प्रशासन लाचार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के कारण एक जिले में बड़े साहब बहुत परेशान हैं। उन्होंने ऊपर से मिले आश्वासन के कारण कुछ बड़े लोगों को भरोसा दिलाया था कि कुछ भी नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन ऊपर के आदेश के चलते मजबूरी है। करें तो क्या करें? कानूनी राय लेकर भी देख लिया, सुप्रीम अथॉरिटी के निर्देश हैं।

कंसाना ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंसाना ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके सुझावों और समस्याओं पर चर्चा की। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल चर्चा कर कई मामलों का समाधान कराया।

समरसता संदेश को हर पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा संकल्प : कृष्णा गौर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के सामाजिक समरसता, समानता और मानव कल्याण के संदेश को प्रत्येक पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। उन्होंने मंगलवार को बरखेड़ा भेल स्थित श्री संत रविदास मंदिर से संत रविदास कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार संत रविदास के विचारों के प्रचार-प्रसार और सम्मान के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान संत रविदास मंदिर परिसर में 15 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमि-पूजन भी किया गया।

राजधानी में पहली बार 'जेन अल्फा प्रोटेस्ट'

रीजनल स्कूल के सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में मंगलवार को रीजनल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय संगठन में संविलयन किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सैकड़ो छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए। छात्रों ने हाथों में 'सेव डीएमएस' सहित विभिन्न पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद रीजनल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसके गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर संविलयन का विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने मांगें नहीं माने जाने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने इसे राजधानी में किसी शैक्षणिक संस्थान के मुद्दे पर पहला 'जेन अल्फा प्रोटेस्ट' बताया। प्रदर्शन में छात्रों ने रीजनल स्कूल की शैक्षणिक पहचान और प्रयोगात्मक स्वरूप को बनाए रखने की मांग की।

डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल डीएमएस को हिंदी में प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय कहा जाता है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि यह सामान्य विद्यालय नहीं है, बल्कि शिक्षा में प्रयोग और नवाचार के लिए इसकी अलग पहचान है। एनसीईआरटी के अंतर्गत ऐसे विद्यालय भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में संचालित होते रहे हैं।

अभिभावकों ने केंद्रीय विद्यालय की प्रवेश नीति को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रवेश की प्राथमिकताएं अलग होने के कारण मौजूदा और भविष्य के विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि इतने बड़े निर्णय से पहले छात्रों और अभिभावकों से चर्चा की जानी चाहिए थी।

कार्रवाई *भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई*

हाईकोर्ट के आदेश पर निशातपुरा में 13 मकान ध्वस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के निशातपुरा स्थित फिजा कालोनी से मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर बने 13 मकानों को ध्वस्त कर दिया। करीब 15 हजार वर्गफीट जमीन पर बने इन मकानों को चार पोकलेन मशीनों की मदद से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान रहवासियों ने विरोध और हंगामा किया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

रहवासियों का कहना था कि वे वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं और उन्होंने नियमानुसार जमीन की रजिस्ट्री भी कराई है। मकान टूटने से उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। महिलाओं ने भी कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी।

बैरागढ़ एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह सहित अन्य राजस्व अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यह अतिक्रमण करीब 35 साल पुराना था। प्रशासन इससे पहले भी कार्रवाई के लिए पहुंचा था, लेकिन विरोध के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की सख्ती की चेतावनी के बीच मंगलवार को कार्रवाई की गई।

दरअसल अविनाश जौहरी की करीब 0.75 एकड़ निजी जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण था। जमीन पर 11 मकान बने थे और कुछ तीन मंजिला मकान भी थे। जौहरी ने जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर, नगर निगम और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिन पक्षकारों को स्थगन मिला है, उन्हें छोड़कर अन्य निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। निशातपुरा में 0.3 एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जे की जानकारी है। कुछ मामलों में हाईकोर्ट का स्थगन होने के कारण फिलहाल वहां कार्रवाई नहीं की गई।

हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताः सीएम

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर किसान के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचाना है, ताकि फसलों को सिंचाई के लिए भरपूर जल उपलब्ध हो सके। किसानों की समृद्धि के लिए सरकार लगातार आवश्यक कदम उठा रही है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

डॉ. यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद सभाकक्ष में खंडवा जिले के किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।